Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्षः 1 अंकः 23 , 13 अक्टुबर, शुक्रवार 2017, सूरत, हिन्दी दैनिक 9879141480 4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

आतंकियो ने अनंतनाग में जम्मू-कश्मीर बैंक से लूटे 5,39,000 रुपये

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुरुवार को आतंकियों ने एक बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर बैंक की मरहमा संगम ब्रांच में पांच लाख से ज्यादा रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने अनंतनाग के मरहमा संगम इलाके में स्थिति जम्मू-कश्मीर बैंक में इस वारदात को अंजाम दिया। बैंक में कुछ हथियारबंद आतंकी घुसे और बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर बैंक से 5,39,000 रुपये की रकम लूटकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद से घाटी में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि इससे पहले 31 जुलाई अक्टूबर को भी आतंकियों ने बैंक की लूटपाट को अंजाम दिया था। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने दिनदहाड़े बैंक में तीन से चार आतंकियों ने बुर्का पहनकर जम्मू और कश्मीर बैंक की एक शाखा में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। आतंकियों ने बैंक से 5.20 लाख रुपये लूटे थे हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।

पटाखा बिक्री पर बैन : कोर्ट से की पुनर्विचार की अपील

नई दिल्ली। पटाखों की बिक्री पर 31अक्टूबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को सदर बाजार में सैकड़ों कारोबारियों ने धरना प्रदर्शन किया। फायरवर्क ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन में सदर बजार, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, लोनी, रोहिणी, द्वारका समेत एनसीआर के पटाखा कारोबारी शामिल थे। प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है जिसकर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि कोर्ट धार्मिक आस्था और कारोबारियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पटाखे बेचने की अनुमति दे सकती है। उन्होंने कहा कि अभी भी अगर हमें पटाखे बेचने की अनुमति मिल जाती है तो कारोबारियों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। प्रदर्शन में शामिल अन्य कारोबारियों ने कहा कि उन लोगों को कोर्ट के आदेश के बाद ही लाइसेंस मिला और उसके बाद ही उन लोगों ने पटाखे मंगवाए। अब अगर बेचने की अनुमति नहीं होगी तो इसे रखना भी गैर कानूनी होगा। ऐसे में हम क्या करें। प्रदर्शन कर रहे कई दुकानदारों ने तो कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी और मां के गहने रख कर पैसे उधार लेकर पटाखे मंगवाए थे। किसी ने कहा कि वह ऊंची सूद पर इस उम्मीद पर पैसे उधार लिए थे कि दीपावली के बाद उसे लौटा देंगे। पर अब हालत बहुत खराब हो गए हैं। अगर पटाखा बिक्री की अनुमति नहीं मिलती है तो सैकड़ों कारोबारी बर्बाद हो जाएंगे।

सांसद के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा

नई दिल्ली। साउथ एवेन्यू थाने में राज्यसभा सांसद के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा एक महिला ने कोलकाता में दर्ज कराया। इसके बाद जीरो एफआईआर में दर्ज मामले को साउथ एवेन्यू थाने को स्थानांतरित कर दिया गया है।पुलिस सूत्रों की मानें तो राज्यसभा सांसद के खिलाफ एक महिला ने दर्ज कराए गए मुकदमे में दावा किया है कि उसके साथ सांसद ने दुष्कर्म किया और मुंह खोलने पर धमकी दी। उसने इस बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस को आपबीती बताई थी, जिसके बाद सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चूंकि दुष्कर्म नई दिल्ली में किए जाने का दावा किया है इसलिए मामले की जांच का जिम्मा साउथ एवेन्यू पुलिस को दिया गया है। आरोपी सांसद वामपंथी विचारधारा के बताए जाते हैं।

फीफा अंडर 17 फुटबाल मैचों के लिए मेट्रो ने की विशेष व्यवस्था

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो ने फीफा अंडर 17 फुटबाल विश्व कप के राजधानी के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 12 और 16 अक्टूबर को होने वाले मैचों को देखने जाने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में दो मैच पहले ही (छह और नौ अक्टूबर) हो चुके हैं। डीएमआरसी के अनुसार विशेष व्यवस्था के अनुसार अब इस लाइन पर रात 11 बजे तक मेट्रो ट्रेन हर 3 मिनट 20 सेकंड में मिलेगी जबकि सामान्य दिनों में ट्रेनों की यह फ्रीक्वेंसी शाम साढ़े आठ बजे तक की होती है और इसके बाद ट्रेन ज्यादा समय के अंतराल पर मिलती है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावः

9 नवंबर को वोटिंग, 18 दिसंबर को आएंगे नतीजे

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम आगामी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। प्रदेश की सभी 68 सीटों पर मतदान 9 नवंबर को कराए जाएंगे। वहीं, नतीजे 18 दिसंबर को घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि इस बार सभी बूथों पर VVPAT मशीन का इस्तेमाल होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 7521 पोलिंग बुथ पर कराया जाएगा। वहीं, चुनाव आयोग ने साफ किया कि आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन, रैली और जुलूस की वीडियोग्राफी होगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने संकेत दिए थे कि गुजरात चुनाव दिसम्बर में हो सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (ष्टश्वष्ट) अचल कुमार ज्योति की मानें तो गुजरात में 50 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान सत्यापन पर्ची (VVPAT) प्रणाली का प्रयोग होगा। इसके अलावा आयोग पहली बार इन चुनावों में महिलाओं के लिए मतदान केंद्र बनाने जा रहा है। ज्योति ने चुनाव

दिसंबर में होने की मीडिया में आई खबरों और कुछ नेताओं के दावे से जुड़े सवाल पर कहा, 'चुनाव दिसंबर में होंगे क्योंकि वर्तमान गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में खत्म हो रहा है।' उन्होंने इस बारे में कुछ कहने से मना किया कि चुनाव एक चरण में होगा या एक से अधिक में। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गुजरात दौरे के दौरान एकत्रित इनपुट पर विचार करेगा। इस टीम में चुनाव आयुक्त ओपी रावत और सुनील अरोड़ा सहित 12 अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

चुनाव आयोग को मिले ये सुझाव

दरअसल चुनाव आयुक्त ने भाजपा, कांग्रेस सहित विविध राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुनाव सुधार संबंधी सुझाव मांगे हैं। इसमें कहा गया है कि विधानसभा चुनाव 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच करवाए जाएं क्योंकि उन दिनों कोई हिंदू शादी नहीं होती। चुनाव आयोग को सौंपे गए मेमौरेंडम में कहा गया है कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच के वक्त को हिंदू धर्म की शादी के लिए सही नहीं माना जाता वहीं 10 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ज्यादा समारोह होते हैं। ऐसे में 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच किसी तारीख में चुनाव करवाए जाने चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि यह वक्त वोटरों और सभी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों के लिए सबसे सही रहेगा। इस तर्क के समर्थन में कहा गया है कि चुनाव को त्योहार की तरह मनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी करें। कहा गया है कि दिसंबर में शादी के सीजन की वजह से एनआरआई भी अपने घर आए हुए होते हैं। वहीं कांग्रेस ने संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने व वीवीपैट के 10 फीसदी वोट गिनकर ही परिणाम घोषित करने की मांग रखी थी। गुजरात चुनाव के लिए अक्तूबर में आ सकती है आप उम्मीदवारों की पहली सूची गौरतलब है कि लगभग 70 लाख की जनसंख्या वाले इस खूबसूरत राज्य में चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 24 लाख 98 हजार 173 जहां पुरूष मतदाता हैं वहीं 24 लाख 7 हजार 492 महिला मतदाताओं की संख्या है। 12 जिलों वाले इस पर्वतीय राज्य में पर्यटन और बागवानी राज्य के मुख्य आर्थिक श्रोत हैं।

अभी दो से तीन दिन तक रहेगी ऐसी स्थिति

नई दिल्ली। गुरुवार की सुबह दिल्ली में लोगों की सुबह ने उन्हें साल 2016 में छाए स्मॉग की याद दिला दी। धुंध की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थीं लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो यह स्मॉग नहीं है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह स्मॉग नहीं है लेकिन सिर्फ धुंध है जो अगले दो से तीन दिनों तक जारी रह सकती है।

क्यों यह सिर्फ धुंध है और स्मॉग नहीं

अधिकारियों ने बताया है कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा, धुंध में कमी आ जाएगी। पिछले साल दीपावली पर स्मॉग छा गया था, जिस कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई।साधारणतया तौर पर कोहरे की स्थिति तब होती है जब विजिबिलिटी 200 मीटर से कम होती है। मौसम विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक सफदरजंग ऑब्जरवेटरी में सुबह 8.30 बजे विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी और ऐसे में इसे स्मॉग नहीं माना जाता। यह सिर्फ धुंध थी। उनका कहना था कि उमस ज्यादा होने की वजह से और रात के तापमान में कमी होने की वजह से सुबह धुंध छाई हुई थी।

सीरियल किलरः 6 साल में 20 महिलाओं का मर्डर,

कोर्ट ने फांसी की सजा उम्रकैद में बदली

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीरियल किलर के दोषी मोहन कुमार की अनीता हत्या मामले में फांसी की सजा को गुरुवार को उम्रकैद में तब्दील कर दिया। मोहन ने वर्ष 2003 से 2009 के बीच 20 महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी सायनाइड युक्त टेबलेट देकर हत्या कर दी थी। न्यायमूर्ति रवि मालिमठ और न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा की खंडपीठ ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि मोहन कुमार को ताउम्र रिहा न करें और उसे किसी तरह की छूट न दें। मोहन कुमार ने वर्ष 2009 में अनीता से शादी का वादा करके उसे बंटवाल से हासन ले गया।

उसने अनीता के साथ बलात्कार किया और उसे एक बस स्टैंड पर ले गया। वहां उसने अनीता को गर्भ निरोधक टेबलेट दिया जो सायनाइड युक्त थी। टेबलेट खाने के बाद अनीता की मौत हो गई। मोहन कुमार ने वर्ष 2003 से 2009 के बीच 20 महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी सायनाइड युक्त टेबलेट देकर हत्या कर दी थी। उसे चार मामलों में आजीवन कारावास की सजा तथा तीन प्रकरणों में फांसी की सजा सुनाई गई है। मोहन कुमार ने फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी।

आरुषि हत्याकांडः

1,417 दिनों बाद डासना जेल से रिहा होंगे तलवार दंपति, हाईकोट ने किया बरी

इलाहाबाद। देश के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में नूपुर और राजेश तलवार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने तलवार दंपति की अपील पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। सीबीआई की निचली अदालत के सजा सुनने के 1,417 दिनों बाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया है। इस मामले में न्यायमूर्ति बी.के.नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर राजेश तलवार और नुपूर तलवार को सजा नहीं सुनाई जा सकती है। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई की जांच में कई खामिया पाई और इस आधार पर तलवार दंपति को बरी कर दिया। गौरतलब है कि डॉ. तलवार की बेटी आरुषि की हत्या 15 एवं 16 मई 2008 की दरम्यानी रात

नोएडा के सेक्टर 25 स्थित घर में ही कर दी गई थी। घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था। इस हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 23 मई को डॉ. राजेश तलवार को बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच एक जून को सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई की जांच के आधार पर गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से तलवार दंपति जेल में बंद हैं।

महंगी होगी बिजली, शहरी नहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ेंगी। नियामक आयोग ने पॉवर कारपोरेशन के प्रस्ताव पर जनसुनवाई करते हुए इसके संकेत दे दिए हैं। गुरुवार को लखनऊ में जनसुनवाई हुई। आयोग के अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने सुनवाई के बाद बिजली चोरी रोकने, गांवों में शत प्रतिशत मीटर लगाने, लाइन हानि रोकने और वितरण व्यय घटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनियों के अनावश्यक घाटे और गरीबों-ग्रामीणों की बिजली का बोझ अब शहरी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।

बिजली विभाग नेकहा दरें बढ़ाना जरूरी-

पॉवर कारपोरेशन की ओर से प्रतिनिधि मध्यांचल के एमडी एपी सिंह ने कहा कि कुल बजट का 80 प्रतिशत बिजली खरीद और ट्रांसमिशन में खर्च किया जाता है। वर्तमान में बिजली 6.97 रुपये प्रति यूनिट खरीद कर दो रुपये तक में दी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 66 हजार करोड़ चाहिए होंगे। प्रस्तावित दरों पर बिल वसूली और सरकार से मिली सब्सिडी के बाद भी 10 हजार करोड़ रुपये का अंतर रह जाएगा। उन्होंने कहा इसमें छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। आयोग को दिए प्रस्ताव में कॉर्पोरेशन ने बिजली दरों में लगभग 22 फीसदी की बढ़ोतरी करने की मांग की है।

कंपनियों पर भड़के आम उपभोक्ता-

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा हवाई अड्डा बनाने वालों को चार रुपये प्रति यूनिट और किसानों को 5-6 रुपये प्रति यूनिट देना कैसे न्याय संगत है? गरीबों-गांवों के 84 लाख उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली के लिए सरकार से मिली 3,760 करोड़ सब्सिडी का आकलन किया जाए तो प्रति उपभोक्ता लगभग373 रुपये आता है। 180 रुपये फिक्स चार्ज और अन्य दरें जोड़ ली जाएं तो यह लगभग 600 रुपये प्रतिमाह पड़ता है। इसलिए अब इसमें और बढ़ोतरी की जरूरत नहीं।

राजभवनों में मूल्यों एवं आदर्शों के स्थापित होने से समाज के लोग प्रेरणा लेंगेः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि सहकारी संवाद के परिप्रेक्ष्य में राज्यपालों का संवैधानिक दायित्व है जो केंद्र एवं राज्यों के बीच सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे में राजभवनों में मूल्यों एवं आदर्शों के स्थापित होने से समाज के लोग प्रेरणा लेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के 48वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि साल 2022 में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण संकल्प इस सम्मेलन में तय किये जा रहे हैं । 2017 से 2022 की अवधि न्यू इंडिया के निर्माण के लिए हैं, जहां भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा और अस्वच्छता के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा, ऐसे में राष्ट्रीय लक्ष्यों को निश्चित समय सीमा में प्राप्त करने के लिए टीम इंडिया एक ही दिशा में आगे बढ़े। कोविंद ने कहा कि सहकारी संवाद के परिप्रेक्ष्य में

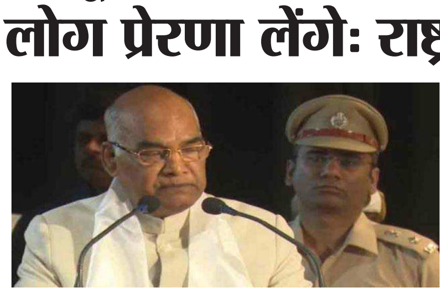

राज्यपालों का संवैधानिक दायित्व है जो केंद्र एवं राज्यों के बीच सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे में जनता की निगाहें राजभवन पर टिकी रहती हैं। राजभवनों में मूल्यों और आदर्शों के स्थापित होने से समाज के लोग प्रेरणा लेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि वे आशा करते हैं कि इस सम्मेलन में केंद्र-राज्य मिल कर देशवासियों के हित में, विशेषकर युवाओं के हित में एकमत होकर दिशा तय करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक राज्य विकसित होगा तभी भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने की कल्पना साकार होगी । स्वचालन :ऑटोमेशन: तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए उपयोग के संदर्भ में हमें युवाओं के लिए नए अवसर तलाशने होंगे । उन्होंने कहा कि संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियों में शामिल आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । कोविंद ने कहा कि देश के 69फीसदी विश्वविद्यालय राज्य सरकारों की देख-रेख में हैं, जिनमें देश के 94फीसदी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं । राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में योग्य व्यक्तियों की समयबद्ध तरीके से नियुक्ति के रास्ते सुझायें।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाने वाला यह 48वां ऐसा सम्मेलन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार इस बैठक की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में 27 राज्यपाल और तीन उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद थे । इस सम्मेलन का मुख्य विषय न्यू इंडिया 2022 है और भारत इसी वर्ष आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा है।

राष्ट्रपति भवन के बयान में कल कहा गया था कि न्यू इंडिया 2022 में देश के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये आधारभूत संरचना क्षेत्र में अनेकों पहल की जरूरत है। इसी प्रकार से न्यू इंडिया 2022 के लिये कई क्षेत्रों में सेवाओं पर जोर दिया जाना है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्त शहर एवं गांव, प्रदूषण मुक्त पयार्वरण तथा नागरिकों की सुरक्षा शामिल है। सम्मेलन के प्रथम सत्र में न्यू इंडिया 2022 के संदर्भ में नीति आयोग प्रस्तुति देगा। राज्यपाल आधारभूत ढांचे और लोक सेवाओं के विषय पर अपनी बात रखेंगे ।

संसार में ऐसा कोई भी नहीं है, जो नीति का जानकार न हो, परन्तु ज्यादातर लोग उसके प्रयोग से विहीन ही होते हैं -कल्हण

अर्थव्यवस्था की विकास दर

अतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पहले के अनुमान के मुकाबले कम रह सकती है। 2017-18 में विकास दर के 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहले का अनुमान 8 प्रतिशत के करीब था। इन दिनों ऐसे और इतने आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों के काम आ सकते हैं। यह आंकड़ा विपक्ष को नये हथियार दे सकता है। पर एक और आंकड़ा अभी आया है, जिसके मुताबिक अप्रैल-सितम्बर की अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह में करीब 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। गत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले। पर दिन बीतते-बीतते यह सूचना आयी कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती की बात मानते हुए 10 क्षेत्रों में प्रयासों की जरूरत को रेखांकित किया है। इनमें से 4 क्षेत्र हैं-विकास, रोजगार, गैर औपचारिक क्षेत्र और खेती। यानी सरकार को अहसास है कि सब कुछ एकदम ठीक नहीं चल रहा है। कुछ बुनियादी बेहतरी की दरकार है। रोजगार और खेती ये दो क्षेत्र तो ऐसे हैं, जहां त्वरित प्रयासों की जरूरत है। भारत की करीब 50 प्रतिशत आबादी 25 साल से नीचे की है। हर माह करीब 10 लाख नौजवान रोजगार बाजार में दाखिल होते हैं। इनके रोजगार की उचित व्यवस्था बहुत जरूरी है। रोजगार सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक और सामाजिक मसला भी है।

खेती पर विमर्श तो बहुत हो गया। अब कुछ ठोस किये जाने की जरूरत है। संसद का एक विशेष अधिवेशन इस संबंध में बुला लेना चाहिए। इसलिए कि बिना राजनीतिक सहमति के बने कुछ भी महत्त्वपूर्ण न हो पायेगा। रोजगार के मसले पर एक ठोस कार्ययोजना सरकार को सबके सामने रखनी चाहिए। मोदी को भूलना नहीं चाहिए कि अपनी चुनाव रैलियों में वह मनमोहन सिंह से हर साल 1 करोड़ रोजगार सृजन के वादे पर सवाल पूछते थे। चुनाव देर सबेर होने ही हैं और अब सवाल पूछने की बारी दूसरों की है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि आप सिर्फसवाल उछाल के नहीं बच सकते। उन सवालों के जवाब आपको तब देने ही होते हैं, जब आप खुद सरकार में हों। मनमोहन सिंह की सरकार हर साल 1 करोड़ नौकरी न दे पायी और न मोदी सरकार दे पायी। यानी अर्थव्यवस्था में कुछ बुनियादी तौर पर ऐसा बदल गया है कि ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा नहीं पा रहे हैं। सरकार और विपक्ष को इस मामले में एक दूसरे पर प्रहार के अलावा गंभीर चिंतन के लिए आपस में मिल बैठना चाहिए।

कानूनों में अपवाद

सवरेच्च अदालत ने 18 साल से कम उम्र की पत्नी से दैहिक संबंध बनाने के मामले में बड़ा फैसला दिया है। इसके अनुसार नाबालिग पत्नी चाहे तो दैहिक संबंध बनाने के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है, इसको रेप माना जाएगा। पत्नी यह शिकायत एक साल के भीतर कभी भी कराने को स्वतंत्र होगी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के उस अपवाद को मानने से इनकार कर दिया, जिसके तहत 15 वर्ष से ज्यादा उम्र वाली बीवी से संबंध बनाने को रेप नहीं माना गया है। कोर्ट ने माना कि बलात्कार संबंधी कानूनों में अपवाद अन्य अधिनियमों के सिद्धांतों के प्रति विरोधाभासी है। यह बच्ची के अपनी देह पर संपूर्ण अधिकार व स्वनिर्णय के अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि नाबालिग पत्नी के अभिभावक के रूप में पति को ही कानूनी अधिकार प्राप्त है। अब तक यह सब अस्पष्ट है, जिसे कानूनों में संशोधनों द्वारा सरकार को स्पष्ट करने की जरूरत है। विशेषज्ञों को लग रहा है कि यह फैसला बाल विवाह पर सीधा असर डालने वाला साबित होगा। कानूनन लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 साल की उम्र विवाह के लिए तय है।

परिवार कल्याण विभाग के सव्रेक्षणसे उजागर होता है कि कानूनी पाबंदियों के बावजूद अभी भी 27 फीसद नाबालिग बच्चियों के विवाह हो रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि इस फैसले से सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। याद रखने की बात यह है कि अभी कुछ ही समय पहले केंद्र ने वैवाहिक बलात्कार पर दलील दी थी कि इससे विवाह संस्था को खतरा हो सकता है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद 18 साल तक की ब्याहता को इस बात का हक मिल गया कि वह अपने पति के खिलाफ जबरन दैहिक संबंध बनाने पर शिकायत दर्ज करा सके। लेकिन अब भी यह विरोधाभास जस का तस है, जिसके अनुसार 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना गैर कानूनी है। नाबालिग पत्नियों को मिले इस अधिकार के बावजूद यह अधूरा ही कहा जाएगा। वैवाहिक संबंधों की जटिलताओं को लेकर हम अब भी बहुत संकीर्ण सोच रखते हैं। अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ औरतों को कानून से ही उम्मीदें हैं। इसलिए कि अदालती आदेशों पर ही सरकारें स्त्री के पक्ष में कानून बनाने पर विवश होती हैं।

सत्संग

ईश्वर विश्वास

ईश्वर विश्वास एक ऐसी चीज है कि जिससे जीवन दर्शन को उच्चस्तरीय प्रेरणा मिलती है। संसार के सभी प्राणी ईर के पुत्र हैं। कोई न्यायप्रिय, निष्पक्ष पिता अपनी सभी संतानों को लगभग समान अनुदान देने का प्रयत्न करता है। ईर ने अन्य प्राणियों को मात्र शरीर निर्वाह जितनी बुद्धि और सुविधा दी तथा मनुष्य को बोलने, सोचने, पढ़ने, कमाने, बनाने आदि की अनेकों विभूतियां दी हैं। अन्य प्राणियों की और मनुष्यों की स्थिति की तुलना करने पर जमीन-आसमान जैसा अंतर दिखाई पड़ता है। जब सामान्य प्राणी अपनी संतान को समान स्नेह-सहयोग देते हैं, तो ईर ने इतना अंतर किसलिए रखा? इसे समझने में प्रत्येक विवेक संपन्न व्यक्ति को भारी उलझन का सामना करना पड़ता है । तत्वदर्शी विवेक बुद्धि इस विभेद के अंतर का कारण भली प्रकार स्पष्ट कर देती है। मनुष्य को अपने वरिष्ठ सहकारी जेष्ठ पुत्र के रूप में सृजा गया है। उसके कंधों पर सृष्टि को अधिक सुंदर, समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके लिए उसे विशिष्ट साधन उसी प्रयोजन के लिए अमानत के रूप में दिए गए हैं। अपनी विशेषताओं का उपयोग इसी महान प्रयोजन के लिए करना चाहिए। जीवन दशर्न की यह उत्कृष्ट प्रेरणा ईर विास के आधार पर ही मिलती है। जीवन क्या है, क्यों है, उसका लक्ष्य एवं उपयोग क्या है? इन प्रश्नों का समाधान मात्र आस्तिकता के साथ जुड़ी हुई दिव्य दूरदर्शिता के आधार पर ही मिलता है। आस्तिकता का सही स्वरूप समझा जा सके और जीवन-दर्शन के साथ उसे ठीक प्रकार जोड़ा जा सके तो निश्चय ही मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण संभव हो सकता है। यही तो ईर द्वारा मनुष्य सृजन का एकमात्र उद्देश्य है। सभी प्राणी एक पिता के पुत्र होने के नाते सहोदर भाई हैं। एक दूसरे का स्नेह, सहयोग पाने के अधिकारी हैं। आस्तिकता यही मान्यता अपनाने के लिए प्रत्येक विचारशील को प्रेरणा देती है। इसका अनुकरण करके प्राणिमात्र के बीच आत्मीयता की भावना विकसित होती है, एक दूसरे के दुख-दर्द को अपना समझने की आकांक्षा प्रबल हो सकती है। विश्व कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार की भावनात्मक स्थापनाएं अतीव श्रेयस्कर परिणाम प्रस्तुत कर सकती हैं। कहना न होगा कि यह दृष्टिकोण हर दृष्टि से-हर क्षेत्र से उज्ज्वल भविष्य की भूमिका प्रस्तुत कर सकने वाला सिद्ध हो सकता है।

''न्यायाधीश सरकारोन्मुख नहीं होते।'

न्यायाधीशों को ''पिंजरे के तोते' बनाने के वास्तव में प्रयास हुए हैं, तो यह निश्चित ही चिंता का विषय है। जस्टिस जयंत पटेल के कर्नाटक उच्च न्यायालय से बंबई उच्च न्यायालय तबादले और फ्रि वहां से इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजे जाने, वह भी उस स्थिति में जब उनके सेवानिवृत्त होने में मात्रदस महीने शेष बचे थे, के विरोधमें उनके इस्तीफे की खबर से विधिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों को दाल में कुछकाला लगा। जस्टिस पटेल ही थे, जिन्होंने गुजरात के चर्चित इशरत जहां मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

सतीश पेडणेकर

भाजपा सरकार के कार्यकाल में जहां तक सीबीआई का प्रश्न है, तो कुछ खास नहीं बदला है। चूंकि सीबीआई गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंतण्रमें कार्य करती है, और इसलिए ही अगर यह अपने राजनीतिक आकाओं के लिए ''पिंजरे में कैद तोता' सरीखी है, तो ताज्जुब की कोई बात नहीं है। लेकिन न्यायाधीशों का क्या जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्या एक के बाद एक सरकारों ने अपने प्रतिबद्ध न्यायाधीशों से न्यायपालिका को पाट देने के भरसक प्रयास नहीं किए हैं, या साहसी और स्वतंत्र न्यायाधीशों के तबादले संबंधी अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया है? अंतर सिर्फ इतना है कि पहले जहां कार्यपालिका अपने स्तर पर मनमर्जी करती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जब-तब इसे अंजाम देती है, जिसके फैसलों के बरक्स कोईउपाय मौजूद नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा पांच अक्टूबर की इस व्यवस्था से आास्ति मिलती है कि ''न्यायाधीश सरकारोन्मुख नहीं होते।' अवधारणाएं हमेशा सही नहीं होतीं।

अगर न्यायाधीशों को ''पिंजरे के तोते' बनाने के वास्तव में प्रयास हुए हैं, तो यह निश्चित ही चिंता का विषय है। जस्टिस जयंत पटेल के कर्नाटक उच्च न्यायालय से बंबई उच्च न्यायालय तबादले और फ्रि वहां से इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजे जाने, वह भी उस स्थिति में जब उनके सेवानिवृत्त होने में मात्रदस महीने शेष बचे थे, के विरोधमें उनके इस्तीफे की खबर से विधिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों को दाल में कुछकाला लगा। जस्टिस पटेल ही थे, जिन्होंने गुजरात के चर्चित इशरत जहां मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उन्होंने निकाय चुनाव में विलंब का कारण बनने वाले गुजरात अध्यादेश को भी खारिज कर दिया था।

स्थानीय निकायों के चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। उल्लेखनीय है कि अभी कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। ऐसे में एक वरिष्ठन्यायाधीश को अन्यत्र भेजे जाने और वह भी उस स्थिति में जब वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभालने वाले हों तो निश्चित ही तबादले के पीछे की मंशा पर शंका होती है। मोदी सरकार के प्रिय रहे अनेक न्यायाधीशों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इसलिए विवाद अनदेखा नहीं किया जा सकता।

भाजपा सरकार ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के नाम को 2014 में खारिज कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन न्यायाधीश होते। सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस केएम जोसेफके हैदराबाद तबादले पर सहमत नहीं हुई जबकि कॉलेजियम अठारह महीने पहले इस बाबत सिफारिश कर चुका था। समझा जाता है कि सरकार उनके 2016 में दिए उस फैसले से नाखुश थी, जिसमें उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को अमान्य करार दिया गया था। कर्नाटक के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसके मुखर्जी के मामले को ही देखें। मई, 2016 में उनका तबादला उत्तराखंड किया जाना था लेकिन सरकार इसके लिए इच्छुक नहीं थी। सरकार ने जस्टिस मुखर्जी के तबादले पर सहमति दी होती तो आज जस्टिस जोसेफ और जस्टिस पटेल, दोनों को ही वह सब मिला होता जिसके वे हकदार थे। जस्टिस राजीव शंखधर का मामला भी ऐसा ही है, जिनके 2016 में दिल्ली से मद्रास उच्च न्यायालय तबादले पर भी भौंहें तनी थीं। जस्टिस शंखधर ने अपने फैसले में केंद्र के उस ''लुक आउट'नोटिस को अमान्य करार दिया था जो ग्रीनपीस एक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई के खिलाफ जारी किया गया था। अनेक विवादास्पद फैसलों के चलते कॉलेजियम के औचित्य पर संकट मंडराने लगा है। दशकों पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अपने से ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा किए जाने वाले ऐसे तबादलों पर कड़ा रुख अपनाया था। कहा था कि ''सरकार जजों के मनमाने'तबादले नहीं कर सकती और तबादलों में प्रधान न्यायाधीश से मशविरा जरूरी है। किसी न्यायाधीश का तबादला उसे ''झुकाने' का जरिया न बने। कहना यह कि कार्यपालिका का किया जो गलत है, तो वैसा ही कुछकॉलेजियम द्वारा किए गए को भी अनुचित मानना ही होगा। तमाम सरकारें ''घुटने टेकी'न्यायपालिका चाहती हैं। गणतंत्र के अस्तित्व में आने से पूर्व जवाहरलाल नेहरू जैसे कद के राजनेता तक ने संविधान सभा में 10 सितम्बर, 1949 को इस विषय सरकार के विचार पर प्रकाश डाला था : ''सीमाओं के भीतर कोईन्यायाधीश और सर्वोच्च अदालत अपने तई तीसरा चेंबर नहीं बना सकते।

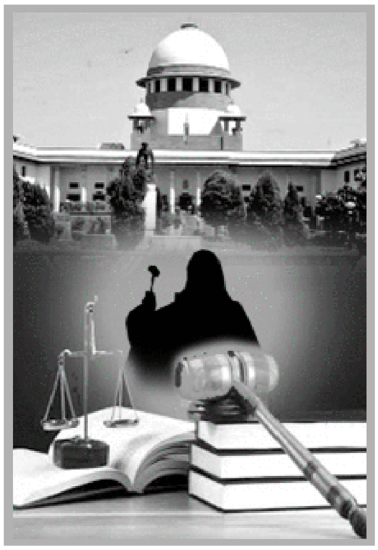

कोई सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका संसद की संप्रभुता का अतिक्रमण करते हुए फैसला नहीं दे सकती। भटकन महसूस हो तो ध्यान अवश्य दिला सकती है, लेकिन संबद्ध समुदाय के भविष्य के मद्देनजर निर्णायक विश्लेषण के आड़े कोई न्यायपालिका नहीं आ सकती। अगर ऐसा करती है, तो स्मरण रहे कि समूचा संविधान ही संसद की निर्मिति है।' उन्होंने सरकार-मुखापेक्षी जज नियुक्त करने की संभावनाओं का उल्लेखकरते हुए कहा : ''यदि अदालत अड़चनकारी साबित हों, तो इससे पार पाने का एक तरीका है ..जजों को नियुक्त करने वाली कार्यपालिका अपनी पसंद के जज नियुक्त करना शुरू कर दे ताकि अपने पक्ष में फैसले करा सके।' जरूरी है कि न्यायपालिका को जवाबदेह बनाया जाए क्योंकि यह तीन मूल्यों को प्रोत्साहित करती है : कानून का शासन, न्यायपालिका में आमजन का विास, और सांस्थानिक दावित्व। दुख होता है कि कॉलेजियम ने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नयन संबंधी सिफारिशें डालेगी बल्कि उनके कारणों का भी खुलासा करेगी। जस्टिस पटेल के इस्तीफे से छिड़े विवाद का ही नतीजा है कि कॉलेजियम को ऐतिहासिक फैसला करना पड़ा है। लेकिन पूछा जा सकता है कि ऐसे सभी मामलों के कारणों को सार्वजनिक किया जाना क्या बुद्धिमत्तापूर्ण होगा क्योंकि इससे तमाम विरोधाभासी संकटों का पिटारा ही खुल जाएगा। तो क्यों न कॉलेजियम को ही ऐसी नीति बनाने दी जाए। शीर्ष जजों के विवेक पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।

चलते चलते

रामलीला

अर्थव्यवस्था लक्ष्मण की तरह मूर्छित पड़ी है, कोई हनुमान जी उसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। पर आज राज चाहे रामलला के भक्तों का हो, लेकिन लगता है संजीवनी लाने वाला कोई नहीं। महाभारत भी तो कहीं इसीलिए नहीं मची। एक तो बूटी की किसी को पहचान नहीं, जो जाहिर है पहले भी नहीं थी, पर तब हनुमान जी का बल काम आ गया था।

रामलीला के दिनों में अचानक महाभारत मच गई है जी! रामलीला के दिनों में यह महाभारत कहीं किसी अनहोनी की तरह तो नहीं आई है? कहां तो गुहार होनी चाहिए थी कि भैया, अर्थव्यवस्था लक्ष्मण की तरह मूर्छित पड़ी है, कोई हनुमान जी उसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। पर आज राज चाहे रामलीला के भक्तों का हो, लेकिन लगता है संजीवनी लाने वाला कोई नहीं। महाभारत भी तो कहीं इसीलिए नहीं मची। एक तो बूटी की किसी को पहचान नहीं, जो जाहिर है पहले भी नहीं थी, पर तब हनुमान जी का बल काम आ गया था। वे पूरा पहाड़ उठा लाए कि लो, इनमें जो संजीवनी हो, वह रख लो। पर इधर तो लगता हनुमान जी ही गायब हैं। किसी को बूटी की पहचान है, और न कोई पहाड़ उठाने वाला है। ऊपर से बीच में ही यह महाभारत मच गया। रामलीला खत्म होने का किसी ने इंतजार नहीं किया। तो रामराज्य स्थापित होने का इंतजार कौन करता ?अब कोई उधर से किसी को शल्य कह रहा है, कोई इधर से किसी को दुयरेधन और दुशासन। अच्छी बात यह कि हैं सब एक ही पाले के। लगता है पांडव पक्ष साफ बच गया। न कोई उनमें से किसी को याद कर रहा है, और न ही किसी पर आरोप। वे तो बस तमाशा देख रहे हैं। समस्या पहचान और भूमिका की आ रही है। शल्य से सबसे ज्यादा दुखी तो कर्ण ही था, जिसका वह सारथी था। कर्ण का उत्साह बढ़ाने के बजाय उसे निराशा में धकेलता रहता था। पर अब जिस पर शल्य होने का आरोप लग रहा है, वह कह रहा है कि मैं तो भीष्म हूं। आप बंदों को पहचान ही नहीं रहे हैं। अब मैं चीरहरण नहीं होने दूंगा। चीरहरण प्रकरण में बेचारा शल्य कहीं नहीं था। फ्रि द्रोपदी की शिकायत ही यह रही कि भीष्म पितामह भी सिर झुकाए हुए बैठे रहे। चीरहरण होता रहा। पर अब अपने को भीष्म कहने वाला चरित्र कह रहा है कि चीरहरण नहीं होने दूंगा। उधर, जिन्हें राम-लक्ष्मण की जोड़ी होना चाहिए था, उनकी पहचान भी दुयरेधन-दुशासन के रूप में हो रही है। ऐन मौके पर हनुमान जी गायब हैं वरना इस वक्त सीना चीर कर दिखा देते कि जिन्हें दुयरेधन-दुशासन कह रहे हो, वास्तव में राम-लक्ष्मण हैं। दुनिया में राजनारायण जी वाली वैराइटी तो अब बची नहीं वरना वे कूदकर सामने आ जाते कि मैं हूं अपने राम का हनुमान।

मुद्दा

व्यावहारिक शिक्षा और बुनियादी तालीम

भारत के पहले राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद् डॉ. राजेन्द्र प्रसाद देश में शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण, शिक्षा से सामाजिक कल्याण, शिक्षा के माध्यम, शिक्षा और सामंजस्य, व्यावहारिक शिक्षा और बुनियादी तालीम जैसे सामाजिक सरोकारों से ताउम्र गहराई से जुड़े रहे। भारतीय शिक्षा को लेकर उनके विचार सदैव प्रासंगिक बने रहते हैं। वे देश के करोड़ों लोगों के व्यक्तित्व की विभिन्नताओं को देश की एकता एवं अखंडता के लिए चुनौती समझते थे, जो देश के विकास में बाधक हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने का काम पुलिस का डंडा या अदालतें नहीं कर सकतीं। अगर यह दूर किया जा सकता है, तो केवल अच्छी शिक्षा द्वारा, और यह काम हमारे विविद्यालय ही कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय विविद्यालयों के एक सरकारी ऑडिट में सलाह दी गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वसटी और बनारस हिन्दू यूनिर्वसटी के नाम से क्रमश: ''मुस्लिम' व ''हिन्दू' शब्द हटा लिया जाए ताकि विविद्यालयों का धर्मनिरपेक्ष चरित्र प्रदर्शित हो सके। भारत के भावी भविष्य के सपने संजोने में देश के दो शिक्षा संस्थानों का गहरा योगदान रहा है। इन दोनों विविद्यालयों को केंद्रीय विविद्यालय का दरजा प्राप्त है, और हजारों विद्यार्थी नियमित यहां से ज्ञानार्जन कर रहे हैं। किसी धर्मनिरपेक्ष देश के शिक्षा संस्थानों में माहौल कैसा हो, यह देखना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि इन दोनों विविद्यालयों की प्रतिष्ठा देश ही नहीं विदेशों में भी है, और अनेक देशों के विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विविद्यालय की स्थापना सन् 1877 में स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत आधार एवं स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर सैयद अहमद खान ने की थी। पहले दिन से ही अरबी, फारसी भाषाओं के साथ-साथ संस्कृत की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। देश की सर्वोत्तम सुविधाओं से शुमार इस विविद्यालय में तकरीबन 25 फीसद विद्यार्थी गैर-मुसलमान हैं। वैसे यहां के गैर-मुस्लिम छात्रों का अनुभव सामान्य नहीं रहता। रमजान शुरू होते ही कैम्पस के भीतर सारी कैंटीन बंद कर दी जाती हैं, जो शाम को इफ्तार के वक्त ही खुलती हैं। यहां तक कि होस्टल में भी यही स्थिति रहती है। कैम्पस में एक मजहब का बोलबाला रहता है। ''यही नहीं शुक्रवार को हाफटाइम के बाद जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी दे दी जाती है। इस दौरान भी सारी कैंटीन बंद हो जाती हैं।' ऐसे में यहां पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम कैसा अनुभव करते होंगे, समझा जा सकता है। काशी हिन्दू विविद्यालय के संस्थापक मालवीय जी को सात्विकता, देशभक्ति, धर्मनिष्ठा तथा सेवा भाव के अद्भुत गुणों के साक्षात अवतार के रूप में याद किया जाता है। इस शिक्षा संस्थान को लेकर मालवीय जी की परिकल्पना में एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष भारत का बेहतर भविष्य रहा होगा जिससे समूचा राष्ट्र मजबूत हो सके। 1905 में इस विविद्यालय को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया और 4 फरवरी, 1916 को बनारस हिन्दू विविद्यालय का शिलान्यास हुआ। वर्तमान में यह विविद्यालय अपनी स्थापना के गौरव को दरकिनार करने के रूप में तेजी से पहचान बना रहा है। काशी हिन्दू विविद्यालय की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर जो रैली निकली थी, उसमें राम मंदिर के नारे लग रहे थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए धर्म, जाति और संस्कृति का सहारा लेने से सदा बचने की हिदायत दी थी।

भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ सबसे बड़ी चुनौती देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र और साझी विरासत को बनाए रखना है। यह शिक्षा संस्थान ही कर सकते हैं, जिसकी बात डॉ.राजेन्द्र प्रसाद ने की थी। भारत के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कथित संस्कृतिवाद को थोपने के प्रयास इस उदार लोकतंत्र के लिए आत्मघाती हो सकते हैं। बहरहाल, केंद्रीय विविद्यालयों के सरकारी ऑडिट की सलाह पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।

परमाणु निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन

आभा स्वामी

जिस समय दुनिया में कई स्थलों पर तनाव खतरनाक रूप ले रहा है, नॉर्वे स्थित नोबेल कमेटी ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को फ्रि से चर्चा में लाने का प्रयास किया है। फ्लिहाल हम उस दौर में हैं, जब चीन ने परमाणु पनडुब्बियों को समुद्री गश्त में लगाने का फैसला किया है, पाकिस्तान गाहे-बगाहे भारत को परमाणु हथियारों की धौंस दिखाता है और अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण का इरादा जताया है। विश्व जनमत की उपेक्षा कर उत्तर कोरिया भी अपनी परमाणु ताकत का लगातार इजहार कर रहा है। वह इसके जरिए न सिर्फअपने आस-पड़ोस, बल्कि अमेरिका को भी धमकाने की कोशिश में लगा है। इस माहौल में वो उद्देश्य विश्व के एजेंडे पर कहीं नजर नहीं आता, जो संयुक्त राष्ट्र के स्थापना प्रस्ताव में व्यक्त हुआ था। वर्ष 1945 में अपने गठन के साथ ही इस संस्था ने दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने का संकल्प लिया था। मगर विडंबना ही है कि उसके बाद परमाणु हथियार रखने वाले देशों की संख्या बढ़ती गई। परमाणु अस्त्र संपन्न देशों का जखीरा भी बढ़ता गया। अब ऐसा लगता है कि विश्व नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के उस मूल उद्देश्य की चर्चा भी छोड़ दी है।

इसी पृष्ठभूमि में इंटरनेशनल कैंपेन टु एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स (आईसीएएन) नामक संस्था को 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। नोबेल कमेटी ने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से होने वाली भयानक मानवीय त्रासदी की तरफ लोगों का ध्यान दिलाने और इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की संधि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आईसीएएन को पुरस्कृत किया गया है। आईसीएएन का गठन 2007 में हुआ। इस वक्त इसकी सहयोगी संस्थाएं 101 देशों में फैली हुई हैं। विगत जुलाई में 122 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियारों पर रोक लगाने वाली संधि को स्वीकार किया। बताया जाता है कि इस संधि को संपन्न कराने में आईसीएएन ने अहम भूमिका निभाई। किंतु उस संधि से विश्व पर मंडराता परमाणु हथियारों का खतरा टला नहीं है। परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत परमाणु अस्त्र संपन्न देश के रूप में मान्यता प्राप्त अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन व फ्रांस इस संधि का हिस्सा नहीं बने। इसी तरह परमाणु हथियार रखने वाले अन्य देश भारत, पाकिस्तान, इसराइल व उत्तर कोरिया भी इसका हिस्सा नहीं हैं। जाहिर है, दुनियाभर में परमाणु हथियारों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाने की जरूरत लगातार बनी हुई है।

भारत ने हमेशा ही परमाणु अस्त्र विहीन दुनिया का समर्थन किया है। लेकिन वह इस मामले में भेदभाव के खिलाफ है। इसीलिए उसने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए और अपनी सुरक्षा का वास्तविक आकलन करते हुए परमाणु हथियार बनाए। अब नोबेल कमेटी ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए मुहिम को बल प्रदान करने कोशिश की है, तो बेशक भारत उसकी भावना के साथ है। क्या बाकी सभी देश भी इस भावना के अनुरूप व्यवहार करेंगे? ऐसा हो, तो अधिक सुरक्षित और खुशहाल दुनिया बनाने का रास्ता साफहो सकता है। लेकिन फ्लिहाल ऐसा होने की गुंजाइश कम नजर आती है।

भाजपा कार्यसमिति की बैठक शुरू, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

कानपुर। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक शुरू हो गई। भौंती स्थित पीएसआईटी के भव्य सभागार में भाजपा के अगुवा नेताओं के बीच प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तय किए गए एजेंडे पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले गेट पर ही अतिथियों का मंत्रोच्चार के बीच तिलक लगाकर स्वागत किया गया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने भाजपा के छह महीने कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। गुरुवार को ठीक 11:15 बजे वंदेमातरम के बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने कार्यसमिति में शामिल सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने प्रदेश कार्यसमिति के प्रस्तावों पर चर्चा शुरू की। बुधवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तय किए गए एजेंडे को सदस्यों के सामने सिलसिलेवार रखा। प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के छह महीने के कार्यों की रिपोर्ट पेश की। बताया कि संगठन ने कैसे लोगों के बीच पैठ बनाने की कोशिश की है। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश के 56 लाख लोगों तक पार्टी ने पहुंच बनाई। नगर निकाय चुनाव प्रदेश कार्यसमिति के मुख्य एजेंडे में रहा। उन्होंने बुधवार को पास किए गए राजनीतिक प्रस्ताव को समिति के सामने रखा। पेश किए गए प्रारूप पर ही प्रदेश कार्यसमिति अलग-अलग सत्रों में शाम पांच बजे तक चर्चा करेगी। इसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद कार्यसमिति प्रदेश अध्यक्ष के रखे प्रस्तावों की पुष्टि करेगी। दोपहर बाद राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

मंच पर मौजूद लोग

मंच पर प्रदेश अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कलराज मिश्र, विनय कटियार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापतिराम त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, प्रदेश सह प्रभारी रमेश बिधूरी, रामेश्वर चौरसिया बैठे हैं। प्रदेश कार्यसमिति में आमंत्रित 468 में से 423 लोग शामिल हुए।

छह घंटा 40 मिनट शहर में रहेंगे सीएम

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ शहर आ रहे है। सीएम गुरुवार को छह घंटा 40 मिनट शहर में रहेंगे।

उनका हेलीकॉप्टर सीधे भौंती स्थित पीएसआईटी कॉलेज के हेलीपैड पर सुबह 10.25 बजे उतरेगा।

शहीद पथ पर चलती टैक्सी कार में लगी आग,चालक ने कूद कर बचाई जान

लखनऊ। शहीद पथ पर चलती टैक्सी कार में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने दमकल पहुंचने से पहले ही आग बुझा ली।

सरोजनीनगर के बेहसा निवासी मोहम्मद एहसान खुद की टैक्सी कार चलाते है। बुधवार दोपहर वह डेढ़ बजे एयरपोर्ट से गोमतीनगर सवारियां छोड़कर लौट रहे थे। आशियाना के रमाबाई चौकी के पास बोनट से धुआं और लपटें उठने लगी। एहसान ने कार से कूदकर जान बचाई। एहसान ने बताया कि छह महीने पहले ही सीएनजी किट लगी गाड़ी खरीदी थी। कार में शार्ट सर्किट होने से आग लगी थी। इस मामले में सीएनजी किट विशेषज्ञ पुनीत जायसवाल का कहना है कि सीएनजी किट लगे वाहनों का रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। बदबू उठने पर फौरन सर्विस सेंटर पर दिखाना चाहिए।

आज़म खान की यूनिवर्सिटी पहुंचा आर्मी टैंक

रामपुर। इंडियन आर्मी की ओर से बतौर उपहार दिया गया चाबुक टैंक बुधवार को जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गया। यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने टैंक का जोरदार स्वागत किया। सड़कें इंडियन आर्मी और जौहर यूनिवर्सिटी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां ने कहा कि आर्मी ने यूनिवर्सिटी को टैंक गिफ्ट में दिया है। पूना से 20 दिन का सफर तय कर टैंक बुधवार को रामपुर पहुंचा, जहां अंबेडकर पार्क पर जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राएं पहले से ही मौजूद थे। जौहर यूनिवर्सिटी और इंडियन आर्मी के नारों से सड़कें गूंज उठीं। यूनिवर्सिटी के गेट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां ने टैंक को रिसीव किया और मेडिकल कॉलेज के सामने ले जाया गया। आजम खां ने टैंक के पास ही मीडिया से बातचीत में कहा कि लोगों को

गलतफहमी थी कि आर्मी से हमारे रिश्ते खराब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्मी ने ही यूनिवर्सिटी को टैंक गिफ्ट किया है, जिससे बच्चे प्रेरित होंगे। यूनिवर्सिटी को सेना के और भी हथियार दिए जाएं, ताकि यहां आर्मी के हथियारों की नुमाइशगाह बन सके।

आर्मी का वकार सियासी दलों से ऊपर है। अब वह आर्मी के परिवार का हिस्सा हैं, उन्हें लड़ाकू विमान, तोपें आदि हथियार भी दिए जाएं।

आजम ने जताया आभार

पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां ने बार-बार इंडियन आर्मी की आभार जताया, लेकिन पूर्व श्रम मंत्री सरफराज खां का भी आभार जताया। बताया कि इनका सराहनीय योगदान रहा है।

चाबुक टैंक

आर्मी ने जौहर यूनिवर्सिटी को चाबुक टैंक गिफ्ट किया है उसे भारत ने वर्ष 1967 में रूस से खरीदा था। इंडियन आर्मी ने टैंक का नाम चाबुक रखा था। आर्मी ने देश भर में छह टैंक दिए हैं। चाबूक टैंक का वजन 60 टन है।

जौहर यूनिवर्सिटी के लिए लाया गया टैंक पूना के किकड़ी शहर से आया है। टैंक 1682 किलोमीटर का सफर तय कर यूनिवर्सिटी पहुंचा।

सेना के अधिकारी आकर इसे हिफाजत से शिफ्ट करायेंगे।

विधानसभा चुनाव की तर्ज पर निकाय चुनाव में उतरेगी भाजपा

कानपुर। भाजपा प्रदेश कमेटी ने तय किया है कि नगर निकाय चुनाव भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर आक्रामक तरीके से लड़ा जाए। यह भी फैसला लिया गया कि सभी की भूमिका तय होनी चाहिए। पार्टी पदाधिकारियों को याद दिलाया गया कि निकाय चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव का रिहर्सल मानें। बुधवार को यहां तिलकनगर स्थित एक होटल में पार्टी की प्रदेश कमेटी की बैठक में राजनीतिक एजेंडे के साथ नगर निकाय और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई।

शाम पांच बजे शुरू हुई बैठक में मुख्य मुद्दा नगर निकाय चुनाव ही रहा। प्रदेश पदाधिकारियों ने इसके लिए प्रत्याशी चयन पर घंटों मंथन किया। जिताऊ-टिकाऊ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति पर दांव लगाने पर जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवप्रकाश तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रत्याशी चयन का प्रारूप तय किया गया। टिकट वितरण में जातिगत समीकरण, व्यक्तिगत छवि, जीतने की संभावना तथा इलाके में पकड़ को आधार बनाया जाएगा। नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगमों के लिए प्रत्याशियों के चयन में पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई गई।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि जिताऊ चेहरे को पार्टी का टिकट दिया जाए। टिकट बंटवारे में पार्टी पदाधिकारियों की भूमिका तय होनी चाहिए। टिकट के मानक तय होने चाहिए।

अयोध्या: केंद्र ने रामायण सर्किट के लिए 133 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अयोध्या में रामायण सर्किट के पुनरुद्धार के लिए 133 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। स्वदेश दर्शन नाम के शुरू की जाने वाली इस योजना में रामायण सर्किट में तमाम निर्माण होने हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए 26 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि एनजीटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर सरयू तट पर भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा का निर्माण भी कराया जाएगा।

जरूरी नहीं है कि बड़े अपराधियों को जेल भेजा जाए, उन्हें जहां होना चाहिए भेजिए: सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें प्रदेश छोड़ने के लिए विवश किया जाए। उन्होंने सर्वे करके प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को बाहर भेजने का निर्देश भी दिया। उनके इस निर्देश को अवैध बांग्लादेशियों व रोहिंग्या मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने पीएसी की खत्म कर दी गई 73 कंपनियां फिर से गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार शाम को लखनऊ में कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने एसओ से लेकर एडीजी जोन तक को प्रतिदिन पैदल गश्त कर जनता से संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थानेवार संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बनाकर उनकी निरन्तर निगरानी करें। उन्होंने कहा कि दीपावली एवं छठ पूजा में कोई भी अप्रिय घटना घटित हुई तो संबंधित पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलों के एसएसपी डीएम से परामर्श कर मेरिट के आधार पर थानाध्यक्षों की तैनाती करें और निठल्ले, लापरवाह व संवेदनहीन थाना प्रभारियों को चिह्नित कर बाहर का रास्ता दिखाएं। मुख्यमंत्री ने पीएसी की 273 कंपनियों में से जनशक्ति के अभाव में खत्म कर दी गई 73 कंपनियों को समयबद्ध ढंग से जल्द से जल्द पुनर्गठित करने का निर्देश भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलावार ट्रैफिक प्लान बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि बस्तियों में संचालित पटाखों की दुकानों एवं गोदामों को कतई संचालित न होने दिया जाए। अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों पर विशेष निगरानी रखकर संदिग्ध व्यक्तियों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जाए। जेल में बंद अपराधियों पर भी कड़ी नजर रखी जाए ताकि वे जेल में रहकर किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न देने पाएं।

बिहार

गांधी मैदान व बोधगया ब्लास्ट के आरोपित तौफिक अंसारी को तीन साल की सजा

पटना सिटी। गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपित तौफिक अंसारी को तीन साल की कैद की सजा सुनायी गयी है। उसे गया के महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का भी दोषी पाया गया है। इस मामले में भी उसे तीन साल की सजा सुनायी गयी है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। बुधवार को गायघाट स्थित किशोर न्याय बोर्ड ने सजा सुनायी।

किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान सदस्य दिव्यामिता ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित को पटना के गांधी मैदान और गया के महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का दोषी माना। दोनों मामलों में तीन-तीन साल की सजा सुनायी। घटना के समय था नाबालिग : 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। घटना के वक्त आरोपित नाबालिग था। हालांकि अब वह 19 वर्ष का है। बुधवार को सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से अधिवक्ता ललन प्रसाद सिन्हा व संजय कुमार ने बहस में भाग लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से 40 गवाह पेश किए गए थे।

ब्लास्ट में आधा दर्जन लोगों की हुई थी मौत

गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में आधा दर्जन लोग मारे गए थे, जबकि 89 जख्मी हो गए थे। घटना के तीन माह पहले सात जुलाई 2013 को महाबोधि मंदिर में भी सीरियल ब्लास्ट कर टूरिस्टों को मारने की साजिश रची गयी थी। मंदिर में हुए बम ब्लास्ट में दो लोग जख्मी हो गए थे।

काट चुका है सजा

तौफिक तीन साल की सजा काट चुका है। गांधी मैदान बम ब्लास्ट में अबतक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि महाबोधि मंदिर ब्लास्ट के आधा दर्जन आरोपियों को पकड़ा गया है। जल्द ही दोनों मामलों में फैसला आने की संभावना है।

रिमांड को आवेदन

छत्तीसगढ़ पुलिस ने तौफिक को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उस पर सिमी का सदस्य होने का आरोप लगाया है। गांधी मैदान में घटना के दिन भाजपा की हुंकार रैली थी। इस रैली को प्रधानमंत्री के प्रत्याशी नरेन्द्र मोदी (अब प्रधानमंत्री) संबोधित करने आए थे। उनके आने से कुछ देर पहले लगभग 10 बजे सबसे पहले पटना जंक्शन परिसर के सुलभ शौचालय में एक बम धमाका हुआ। जिसमें एक आरोपित की मौत हो गयी जबकि दूसरा इमतियाज अंसारी को पटना जंक्शन रेल पुलिस के एक सिपाही ने पकड़ लिया था। उसके बाद गांधी मैदान में सभा के दौरान 7 धमाके हुए। इसमें छह की मौत हुई थी।

होटल टेंडर घोटाला: पूछताछ के लिए ईडी नहीं पहुंची राबड़ी देवी, 16 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम

नई दिल्ली। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई। ईडी ने उन्हें रेलवे होटल आवंटन में भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। लगातार यह दूसरा मौका है, जब राबड़ी देवी पूछताछ के लिए नहीं आई।प्रवर्तन निदेशालय ने राबड़ी देवी को फिर नोटिस जारी कर उन्हें 16 अक्तूबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस मामले में करीब साढ़े आठ घंटे तक पूछताछ की थी। रेलवे होटल आंवटन घोटाले में ईडी राबड़ी देवी के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ कर सकता है। इस मामले में सीबीआई पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ कर चुकी है।

जेपी जयंती: नीतीश बोले, बिहार के घर-घर पहुंचाएंगे गांधी का संदेश

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के घर-घर गांधी के संदेश को पहुंचाएंगे। हर घर पर सरकार की ओर से वालेंटियर दस्तक देंगे और बापू आपके द्वार फोल्डर पढ़ कर लोगों को सुनाएंगे। इसके बाद उन्हें फोल्डर भी देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य गांधी के विचारों से खासकर युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। मुख्यमंत्री बुधवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर ज्ञान भवन में गांधी कथा वाचन और बापू आपके द्वार अभियान की शुरुआत करने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने 'बापू आपके द्वार' फोल्डर का भी लोकार्पण किया। कहा कि 10 से 15 फीसदी युवा भी गांधी के विचारों को जानें और उसे आत्मसात करें तो बिहार ही नहीं पूरा देश बदल जाएगा। समाज में बड़ा परिवर्तन आएगा। गांधी

अपने काम से संदेश देते थे, न कि जुबान से। अपने मार्ग पर सदा अडिग रहते थे, चाहे उनके रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए। चंपारण यात्रा के दौरान एक तरफ गांधी ने किसानों को उनकी समस्या से निजात दिलायी तो दूसरी ओर उनलोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए भी प्रेरित किया। छह स्कूल गांधी ने वहां पर खोले और दूसरे राज्यों से भी शिक्षक बुलाकर बच्चों को शिक्षा देना शुरू कराया। छुआछूत के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। हमें अपने कर्म में गांधी के विचारों को अपनाना चाहिए।

गांधी के विचारों की हत्या नहीं हो सकती

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गांधी की हत्या हो सकती है, पर उनके विचारों की नहीं। गांधी अपने मार्ग से कभी अडिग नहीं होते थे।

गांधी कहते थे कि पृथ्वी के पास शक्ति है कि पूरी दुनिया के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। लेकिन लोगों की लालच को पूरा नहीं कर सकती।

शर्मनाक : टॉयलेट गई महिला से रेप की कोशिश, विरोध करने पर ले ली जान

नौबतपुर पटना। पटना के नौबतपुर में बुधवार को दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दिल दहला देनेवाली घटना हुई। महिला ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। नौबतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच को निकली महिला (35 वर्ष) से गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया। घटना के बाद महिला को पहले नौबतपुर पीएचसी पर प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया। वहां से पीएमसीएच रेफर किया गया। पीएमसीएच में प्रसूति रोग विभाग के ऑपरेशन टेबल पर उसने दम तोड़ दिया।

डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक खून बहने के कारण इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। महिला के चार छोटे बच्चे हैं। पति मजदूरी करता है। पुलिस ने आरोपित युवक धीरज कुमार (22 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया।

पीएमसीएच के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता ओटी में महज 8 मिनट ही जिंदा रह पाई। पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि उसके आंतरिक भाग में क्या क्षति हुई है।

नौबतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला शाम तीन बजे शौच के लिए गांव के बधार में गई थी। अकेला पाकर उसी गांव के धीरज ने पहले रेप की कोशिश की। विफल होने पर उसने बहशी तरीके से प्राइवेट पार्ट में लोहे का रॉड डाल दिया। उसके बाद वह मौके से फरार हो गया।

खून से लथपथ एवं दर्द से कराहती महिला किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

छात्र राजनीति के लिए भागलपुर यूनिवर्सिटी लगातार छठे दिन भी बंद

भागलपुर। छात्र संघ चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग पर छात्रों ने बुधवार को छठे दिन भी विश्वविद्यालय बंद रखा। छात्रों ने सभी कालेज और विभागों को बंद कर दिया। विभागों में क्लास कर रहे छात्रों को भी बाहर निकल दिया गया। इसके बाद छात्र अनशन पर बैठ गए। छात्रों ने सभी कालेज और विभागों को बंद कर दिया। विभागों में क्लास कर रहे छात्रों को भी बाहर निकल दिया गया। इसके बाद छात्र अनशन पर बैठ गए। विश्वविद्यालय में 13 और 17 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। छात्र संघ चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग पर छात्रों ने बुधवार को छठे दिन भी विश्वविद्यालय बंद रखा।

केरल में वामपंथियों का सफाया तय : मोदी

पटना। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि हिंसा की बुनियाद पर खड़े वामपंथियों का पूरी दुनिया से सफाया हो चुका है। त्रिपुरा व केरल में सिमटा वामपंथ यहां से भी साफ होगा।

भाजपा द्वारा वामपंथियों की हिंसा के खिलाफ केरल में 15 दिवसीय जनरक्षा पदयात्रा के 10वें दिन इट्टुमनोर से कोट्टयम तक 12 किमी यात्रा के बाद एक जनसभा में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। लेकिन, हमारा विश्वास लोकतंत्र में है। चुनाव से ही इनका सफाया करेंगे। आरोप लगाया कि केरल में सरकार संरक्षति हिंसा से भाजपा व सहयोगी संगठनों के

120 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। केरल के सीएम के गृह जिले में 84 घटनाएं हुई हैं। बिहार में सीपीएम कभी पनप नहीं पाई। जिन इलाकों में कम्यूनिस्टों का प्रभाव था, वहां किसी दूसरे को घुसने नहीं दिया जाता था। भाजपा द्वारा वामपंथियों की हिंसा के खिलाफ केरल में 15 दिवसीय जनरक्षा पदयात्रा के 10वें दिन इट्टुमनोर से कोट्टयम तक 12 किमी यात्रा के बाद एक जनसभा में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। लेकिन, हमारा विश्वास लोकतंत्र में है। चुनाव से ही इनका सफाया करेंगे।

बिहार मौसम: आने वाले दिनों में हो सकती है बारिश, तूफान भी आ सकता है

पटना। बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाकों में बने निम्न दबाव के क्षेत्र कारण पिछले दो दिनों से बिहार के सीमावर्ती सहित विभिन्न जिलों में हुई बारिश का क्रम गुरुवार को थमेगा। दक्षणि-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि राज्य में विभिन्न स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। राजधानी पटना में बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना है।

गया, भागलपुर और पूर्णिया में भी लगभग यही स्थिति रहेगी। इससे पूर्व मंगलवार देर रात और बुधवार शाम तक लगभग सात मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक 190 मिमी बारिश जमुई में दर्ज की गई। इसके अलावा सोनो में 180, सूर्यगढ़ा में 170, झाझा में 140, परबत्ता में 130, बांका, वीरपुर में 110 मिलीमीटर बारिश हुई।

बारिश के कारण राधानी पटना और गया के अधिकतम तापमान में चार से छह डिग्री तक गिरा। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री था जो बुधवार को 28.6 डिग्री पर आ गया। इसी तरह गया का तापमान 31.7 डिग्री से 27.4 डिग्री पर पहुंच गया। भागलपुर के न्यूनतम तामनान में गिरावट दर्ज की गई। 24 से तापमान 21.8 डिग्री पर आ गया।

बारिश के कारण राधानी पटना और गया के अधिकतम तापमान में चार से छह डिग्री तक गिरा। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री था जो बुधवार को 28.6 डिग्री पर आ गया।

इसी तरह गया का तापमान 31.7 डिग्री से 27.4 डिग्री पर पहुंच गया। भागलपुर के न्यूनतम तामनान में गिरावट दर्ज की गई। 24 से तापमान 21.8 डिग्री पर आ गया।

सूरत। अपनी विविध मागों को लेकर हड़ताल पर उतरे आपातकालीन सेवा 108 के कर्मचारियों ने गुरूवार को चौक बाजार स्थित जूनी सिविल हास्पीटल कैम्पस की सफाई कर अपना विरोध प्रदर्शन किया।

मेयर अस्मिताबेन सिरोया की अध्यक्षता में हुआ गरीब कल्याण मेले का आयोजन

बारडोली के बाबेन में मंत्री नानूभाई वानाणी के हाथों जरूरतमंदों को मिली सहायता

स्सूरत। गरीबों को तत्काल उनका हक्क दिलाने के उद्देश्य से आयोजित गरीब कल्याण मेले का गुरुवार को शहर की मेयर अस्मिताबेन सिरोया की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मेयर सहित अन्य महानुभावों के हाथों कुल 17,655 जरूरतमंदों को 349.52 करोड़ की साधन सामग्री प्रदान की गई। नानपुरा गांधी स्मृति भवन में आयोजित गरीब कल्याण मेले में सारकार के समाज सुरक्षा, नायब नियामक विकसित जाति, नायब नियामक अनुसूचित जनजाति, जिला उद्योग केंद्र, मामलतदार कार्यालयों, श्रमयोगी कल्याण बोर्ड तथा मनपा के विभिन्न 11 विभागों की 47 योजनाओं के तहत 17,655 जरूरतमंदों को 349.52 करोड़ के लाभ प्रदान किए गए।

इस अवसर पर मेयर ने कहा कि राज्य सरकार तथा सूरत महानगरपालिका द्वारा 2009 से शुरु किए गए गरीब कल्याण मेले की यात्रा को 16 साल हो गए। जिसके तहत गरीब तथा जरूरत मंदों को अलग-अलग योजनाओं के तहत सुविधायुक्त घर , पानी, बिजली मिलती रहे इस दिशा में राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। 2022 तक सबको खुद का घर मिल सके यह प्रधानमंत्री का प्रयास है

फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना अनंतर्गत 5000 मकानों के लिए डीपीआर तैयार कर दी गई है। इस अवसर पर सांसद दर्शनाबेन जरदोश, विधायक रणजीतभाई गिलीटवाला, झंखनाबेन पटेल, जनकभाई पटेल, शासक पक्ष के नेता गिरजाशंकर मिश्रा, स्थाई समिति के चेयरमैन राजेशभाई देसाई सहित जिला तथा पालिका के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन के लिए सरकार कटिबद्ध

महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन के उद्देश्य से सूरत महानगरपालिका के यूडीसी विभाग द्वारा पिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस योजना का लाभ लेने वाली लाभार्थी जैले की पूनमबेन नानूभाई पटेल ने अपना प्रतिभाव व्यक्त करते हुए कहा कि एक समय मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी। 10 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद महीने के 5000 रुपये मिलते थे। जिसमें काम का बोझ ज्यादा तथा पगार कम मिलता था। महानगरपालिका के यूसीडी विभाग द्वारा महिलाओं तालीम देने के बाद दिए जाने के बाद इ-रिक्षा दिए जाने से उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। अब मैं रोज के 500 रुपये रिक्षा चलाकर कमा लेती हूं। इससे मेरे आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी के साथ आर्थिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। गुजरात सरकार की विविध लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक सीधे पहुंच सके इस उद्देश्य से बारडोली तालुका के बाबेन में गुरुवार को जिला स्तरीय गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जलसंपत्ति, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री नानूभाई वनाणी की अध्यक्षता में लाभार्थियों को जरूरत की वस्तुएं वितरित की गई।

बारडोली सुगर फैक्ट्री प्रांगण में आयोजित गरीब कल्याण मेले में विविध योजनाओं के तहत 5772 लाभार्थियों को 8.39 करोड़ की साधन सामग्री वितरित की गई।

सचिन जीआईडीसी में दो युवकों पर चाकू से हमला :एक की मौत

सूरत। सचिन जीआईडीसी के रोड नंबर 51 पर देर रात दो युवकों पर उन गाव के युवक ने आपसी रंजीश के चलते चाकू से हमला किया था । दोनो युवको गंभीर अवस्था मे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया । जिसमें से एक युवक की उपचार दौरान मौत होने के चलते पुलिस ने हत्या के मामले दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू की है ।

पुलिस सूत्रों के अनुसार सचिन के शिवनगर स्थित राजदीप सोसायटी निवासी सुमित उमेशसिग चौधरी 25 डाइंग मिल में नोकरी कर परिवार का गुजारा करता था । बुधवार की रात में सुमित सचिन जीआईडीसी की हिन्दुस्तान सिल्क मिलमे मजदूरी काम कर रहा था तथा उन पाटिया के सबनम नगर निवासी हसनरजा नामक आरोपी भी इसी मिलमे काम करता है ।

रात में मिलके ठेकेदार राजेश यादव के साथ पगार के पैसो के चलते आरोपी हसनरजा की कहासुनी होने बाद हाथा पाई होगई इसी बीच मिल का सुपर वायजर जितेन्द्र मोके पर आ पहुचे थे और झगड़े के बीच बीच बचाव करने लगे इसी रंजिश के चलते आरोपी हसनरजा ने जितेन्द्र भाई को चाकू धोपकर भागने लगा । आरोपी को पकडने उसके पीछे सुमित, अजय,तथा जयेश सहित के कामदार दौड़े थे ।और सचिन जीआईडीसी के रोड नंबर 51 पर आरोपी को पकड लिया । जह हाथा पाई होने पर आरोपी हसनरजा ने सुमित को भी चाकू धोपकर फरार हो गया।

सूरत। शहर कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने गुरुवार को सूरत जिला कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले दिनों जिला कलेक्टर द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान यह कहे जाने पर कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी विदेश से पत्नी लाने की क्या आवश्यकता था क्या भारत में औरतों की कमी थी। इसी बात के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने कलेक्टर को बीजेपी का एजेंट बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

जीएसटी के विरोध में अब विविर्स भी नहीं मनाएंगे दिवाली

सूरत। जीएसटी से सूरत कपड़ा मार्केट प्रभिवत हुआ था अब उसके बाद वीवर्स ने भी जी एस टी का विरोध किया है। फोगवा अध्यक्ष अशोक जीरा वाला ने गुरु वार को एक पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकर ने 12 प्रतिशत वीविंग उद्योग पर जी एस टी लाद दिया है पर उस के अनुसंधान ने किसी भी प्रकार का घोषणापत्र जारी नही किया है जिस के चलते विविर्स एकमो के साथ जुड़े व्यापारियों को भी अनेक नुसकेलियो का सामना करना पड़ रहा है ।साथ ही में उन्होंने कहा कि इस वर्ष की दीपावली को वे काली दीपावली के रूप में घोषित करेंगे।

फोस्टा अद्यक्स अशोक जीरा वलने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि यार्न के व्यापार से जुड़े व्यापारियों को 5प्रतिशत जी एस टी लागू किया है जो व्यापैयोको रिफंडेबल है केकिन विवेसो मगर विविर्स को इस तरह की कोई राहत नह मिली है। साथी ही उन्होंने बताया कि वीविंग इकाइयों से जुड़े 88 हजार से अधिक लूम्स मशिने जी एस टी इफेक्ट से बंद होने की कगार पे है। साथ ही में सरकार महिला सशक्तिकरण करने की बात कर रही है तो दूसरी और लूम्स व्यसाय से जुड़ी करीबन 2लाख महिलाये बेरोजगार हो गई है।

सूरत। अंबाजी मंदिर की 49वीं वर्ष गांठ पर गुरुवार को अंबिका निकेतन अठवालाइंस में अन्नकूट दर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता के समक्ष विविध प्रकार के पकवान व प्रसाद सामग्रियों का भोग लगाया गया।

साध्वी श्री मधुबालाजी के सानिध्य में जैन जीवन शैली कार्यशाला आयोजित

सूरत। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन से सूरत जिला मंडल में साध्वी श्री मधुबालाजी के सानिध्य में जैन जीवन शैली कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत श्री सपन्नो स्याम्म के अनुष्ठान से किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल की बहनों द्वारा नौ आयामों जैन जीवन शैली के नाटक द्वारा प्रस्तुत किया। साध्वी मधुबाला ने कहां कैसे चले, कैसे खाए, कैसे सोयें जिससे हमारे जीवन में पाप कर्म के बंधन न हो। स्वागत वक्तव्य अध्यक्ष सुनीती सुराणा ने दिया।

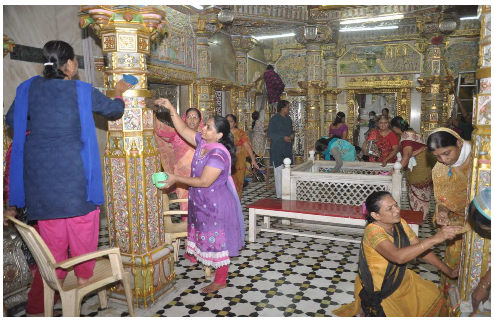

सूरत। दीपावली के उपलक्ष्य में गोपीपुरा स्थित जैन देरासर की सफाई करती महिलाएं।

सूरत। आईएनआईएफडी की छात्राओं द्वारा गुरुवार को अठवागेट प्रांगण में ड्रेस मेकींग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें संस्थान की छात्राओं ने फैशन डिजाइनिंग के नए-नए नमूने पेश किए गए।

शहर के 50 पीएसआई के तबादले

सूरत सहित राजय से 515 पीएसआई के तबादले

स्वतंत्र राजस्थान संवाददाता, सूरत। विधान सभा के चुनाव के आगमन के पहले ही राज्य भरकी पुलिस के तबादले करने के दौर के बीच आज गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के 515 पीएसआई ओके तबादले के आदेश जारी किया गया। किये गए तबदलेमे सूरत शहर के 50 जीतने पीएसआई के तबादले हुए है ।

पुलिस सूत्रों के अनुसार एक तरफ गुजरात मे होने वाले विधानसभा के चुनाव की तारीख अबतक सामने आया नही है उसी बीच राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस के तबादले के दौर शुरू हुआ है। जिसमे डीवाईएसपी , थाना प्रभारी ओके तबदले हुए थे । इसी बीच गुरुवार के रोज गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के 515 पीएसआई ओके तबदले का ओर्डर जारी किया था । जिसमे सूरत के 50 पीएसआई के तबदले जिले में हुए है ।

मनोपा का आरोग्य विभाग आया हरकत में:विविध जोनों की फरसाण की दुकानों पर मारे छापे

नमकीन के सेम्पल एकत्र कर भेजे जांच के लिए

सूरत। त्योहार आते ही सूरत महानगर पालिका का हेल्थ एन्ड हॉस्पिटल विभाग अचानक से हरकत में आ जाता है ।गुरु वार को आरोग्य विभाग की टीम ने सूरत के सेंट्रल ज़ोन सहित शहर की अलग क्षेत्रे की फरसाणो की दुकानों पर छापे मारे। वही दुकानों से एकत्र किए नमकीन के नमूनों को जांच पड़ताल के लये भुज व राजकोट की लैब में भेज दिया है ।त्योहार आते ही सुरतकी स्वाद प्रिय जनता फरसाण की दुकानों में खरीदारी के लये लंबी लंबी कतारें लगते है वैसे में जनता की सेहत के साथ किसि भी प्रकर का खिलवाड़ न हो उस की सावधानी भी मनपा रखती है।

मंनपा की आरोग्य विभाग की टीम ने सूरत शहरके सेंट्रल जॉन में भागल विस्तार की वेलकम फरसाण,भस्तान की ठक्कर फ़ूड,उधना क्षेत्र की विधाता फ़ूड,वेड रॉड के प्रख्यात दास पेड़े वाला की नमकीन दुकान पर छापेमारी की वही दूसरी औए लीबायत,वराछा और एके रॉड स्थित की नमकीन दुकानों पर छापे मेरी की । वही दुकानों से एकत्र किए नमकीन के नमूनों को जांच पड़ताल के लये भुज व राजकोट की लैब में भेज दिया है ।त्योहार आते ही सुरतकी स्वाद प्रिय जनता फरसाण की दुकानों में खरीदारी के लये लंबी लंबी कतारें लगते है वैसे में जनता की सेहत के साथ किसि भी प्रकर का खिलवाड़ न हो उस की सावधानी भी मनपा रखती है।

हेल्थ विभाग की इस छापे मेरी से नमकीन दुकानदार में हड़कंप का माहौल देखनेको मिला था ।उल्लेखनीय है कि बुधवार को मनपा की आरोग्य विभाग की टीम ने शहर। की अलग अलग बेकरियों पर छपे मेरी की थी।

सूरत। सूरत महानगर पालिका द्वारा दिपावली के उपलक्ष्य में शहर की सड़को तथा सामुदायिक भवनों की रगाइ पुताई का काम शुरु कर दिया गया है। शहर के फलाईओवरों के उपर जहा विद्युत लड़ीया साजाई जा रही है वहीं बीआरटीएस के ग्रीलों का रंग रोगन किया जा रहा है।

सूदखोरों से प्रताड़ित होकर बिल्डर ने की खुदकुशी कोशिश

सूरत। उधना गांव निवासी एक बिल्डर ने अपने पांडेसरा स्थित कार्यालय में नीद की अधिक गोलिया गतकर खुदकुशी की कोशिश करने से सनसनी फैल गई है । पीड़ित को सूदखोर द्वारा पिछले काफी समय से अधिक व्याज के लिए प्रताड़ित किया जारहा था । फीलाल पीड़ित को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया न्यू सिविल अस्पताल के अनुसार उधना के महादेव फलिया निवासी अजय भाई प्रवीण भाई वशी 48 बिल्डर है । पांडेसरा के अवधूत दर्शन कॉम्प्लेक्स में अजयभाई का कार्यालय आया है । गुरुवार की दोपहर अजयभाई ने अपने कार्यालय में नीद की 20 से अधिक गोलिया निगल कर खुदकुशी की कोशिश की है । अजयभाई को तत्काल उपचार के लिए न्यू सिविल अस्पताल में लाया गया । जहा से अधिक उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया । इस मामले में पीड़ित अजयभाई ने भरत, तिवारी तथा केजरीवाल सहिय तीन सूदखोरो के खिलाफ आरोप लगाया है कि बिल्डर के कंट्रक्शन काम के लिए सुधखोरो के पास 50 लाख तथा 20 लाख रुपये व्याज से लिये थे । तीनो को मुद्दल की पूजी से अधिक 1 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा देने के बाद भी अधिक पैसो के लिए प्रताड़ित करते थे । हादसे के चलते उधना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू की है...

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास,सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं तापीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) E-mail: krantisamay@gmail.com